(iii) The release mechanism for free sale sugar has been regulated in such manner so as to ensure adequate realisation to the sugar factories.

(iv) Special releases have been allowed to sugar factories which were having high cane price arrears.

(v) Control on price and movement of molasses has been lifted. This will help to industry in earning additional revenue.

(d) No, Sir. However, a Group has been constituted to review the procedure for conversion of Letters of Intent into Industrial Licences, issue of completion certificates and release of incentives to sugar factories set up after grant of Letters of Intent.

(e) Government has taken the following steps to increase sugar production during 1993-94 season:

(i) The Statutory Minimum Price (SMP) of sugarcane for 1993-94 season has been raised to Rs. 34.50 per quintal linked to a basic recovery of 8.5 per cent, as against Rs. 31.00 per quintal for the season 1992-93.

(ii) The Government has announced incentives in the form of additional free sale quota for early, mid and late crushing.

(iii) State Governments have been requested to consider imposing a ban on the operation of gur and khandsari units before 31st December, 1993 to ensure optimum availability of sugarcane to sugar mills.

The Committee constituted to formulate development programme for sugar industry for the 8th Five Year Plan had recommended a sugar production target of 127.76 lakh tonnes for the sugar year 1993-94.

खाद्यान्नों के उत्पादन की मात्रा

1104. श्री शिवचरण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन होता है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा खाद्य पदार्थ-वार उत्पादन में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई होती है ;

(ख) सन् 2000 ईस्वी. तक खाद्यान्नों की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी ;

(ग) खाद्य-पदार्थ-वार कितनी कमी रहेगी तथा देश में अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करके इस कमी को कहां तक पूरा किया जा सकेगा ; और

(घ) क्या यह सच है कि भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की खपत सब से कम है तथा खाद्यान्नों की अनुपलब्धता अथवा आर्थिक निर्धनता के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1992–93 के दौरान देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 180.01 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था । राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

प्रमुख खाद्यान्न फसलों अर्थात् चावल गेहूं, मोटे अनाज, दालों और कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की मिश्रित वार्षिक दर 1980–81 से 1991–92 के दौरान क्रमशः 3.69, 3.59, 0.6, 1.42 और 2.95 प्रतिशत थी ।

(ख) योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार, 2000 ईस्वी तक देश में खाद्यान्नों की कुल जरूरत लगभग 228 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है ।

(ग) अधिकतर खाद्यान्न एक दूसरे के विकल्प हैं । इसलिए, जब तक देश में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन में वृद्धि नियोजित रूप से प्राप्त होती रहे तब तक खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं होगी ।

(घ) किसी देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत लोगों की खाने की आदत

और अन्य खाद्यों, जिनमें पशुधन और समुद्री उत्पाद शामिल है, की उपलब्धता पर पर निर्भर करती है । भारत में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत इसके जैसे ही अन्य देशों से काफी तुलनीय है । देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता समुचित है ।

अनुबंध

विवरण

1992-93 के दौरान कुल खाद्यान्नों का राज्यवार उत्पादन

(लाख मीटरी टन)

आन्ध्र प्रदेश	113.3
अरुणाचल प्रदेश	1.9
असम	34.5
बिहार	91.7
गोआ	1.5
गुजरात	54.1
हरियाणा	102.5
हिमाचल प्रदेश	14.1
जम्मू और कश्मीर	14.1
कर्नाटक	84.9
केरल	11.1
मध्य प्रदेश	163.2
महाराष्ट्र	140.7
मणिपुर	2.8
मेघालय	1.5
मिजोरम	1.0
नागालैंड	2.1
उड़ीसा	69.8
पंजाब	200.1
राजस्थान	113.9
सिक्किम	1.0
तमिलनाडु	84.2
त्रिपुरा	4.6
उत्तर प्रदेश	361.8
पश्चिम बंगाल	126.8
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.3
दादरा और नागर हवेली	0.3
दमन और दीव	0.1
दिल्ली	1.2
पाण्डिचेरी	0.7
समस्त भारत	1800.1

खाद्य मंत्रालय द्वारा अपनाये गये आर्थिक उपाय

1105. **श्री अजीत जोगी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने व्यय में कमी करने के लिए उनके मंत्रालय ने कौन-कौन से आर्थिक उपायों को अपनाया है; और

(ख) इन उपायों को अपनाये जाने से वर्ष 1991-92 में कितनी धनराशि की बचत हुई ?

खाद्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) दूरभाष, स्टाफ कारों, मुद्रित सामग्री के इस्तेमाल, यात्राओं और दौरों आदि के सम्बन्ध में अपनाए गए विभिन्न मितव्ययी उपाय करने और खर्च पर गहरी नजर रखने के फलस्वरूप 1991-92 के दौरान बजटीय प्रावधानों के प्रति लगभग 51.00 लाख रुपए की बचत की गई है।

मध्य प्रदेश में चीनी का उत्पादन

1106. **श्री अजीत पी0के0 जोगी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सितम्बर तक उत्पादित कुल चीनी में मध्य प्रदेश का कितना योगदान रहा है ;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) 1992-93 चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान देश में उत्पादित कुल 106.09 लाख